कृषि क्षेत्र के लिए छह प्राथमिकताओं पर जोर

संजीव मुखर्जी
नई दिल्ली, 2 अगस्त

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र ने कृषि क्षेत्र की वृद्धि के लिए छह प्राथमिकताएं तय की हैं जिनमें उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत कम करना, किसानों को उनकी फसल के लिए उचित कीमत देना, प्राकृतिक आपदा की स्थिति में किसानों को उपयुक्त राहत राशि देना और कृषि क्षेत्र में विविधता लाने के साथ ही प्राकृतिक खेती पर जोर देना शामिल हैं।

राज्य सभा में अपने मंत्रालय के कामकाज से जुड़ी चर्चा पर जवाब देते हुए चौहान ने कहा, 'हम छह सिद्धांतों के आधार पर कृषि के लिए एक रोडमैप बनाने की दिशा पर काम कर रहे हैं।' पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार द्वारा किए गए काम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र किसानों को उनकी फसलों के लिए लाभकारी कीमतें देने के साथ ही यूरिया और डीएपी खाद के लिए सब्सिडी वाली दर देने के लिए प्रतिबद्ध है।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके चौहान ने विपक्षी दलों को इस बात के लिए आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार उनके सभी ठोस सुझावों पर विचार करने के लिए तैयार है और किसानों के कल्याण के लिए इन सभी पर अमल करने की कोशिश की जाएगी।

अपने एक घंटे के भाषण में उन्होंने विपक्षी दलों के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया की बजट में कृषि और इससे संबद्ध क्षेत्रों के लिए फंड के आवंटन में कमी की गई है। उन्होंने कहा

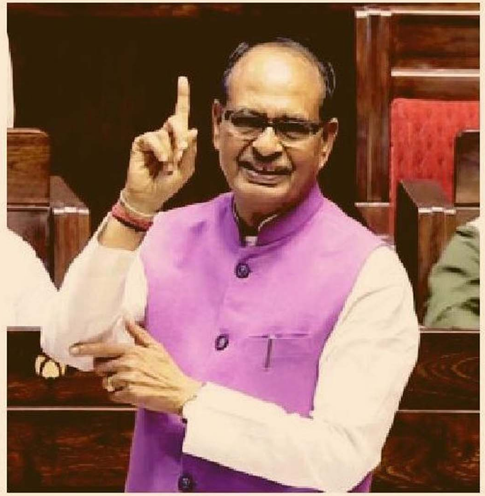

नई दिल्ली में मॉनसून सत्र के दौरान राज्य सभा में बोलते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान *-पीटीआई*

कि वर्ष 2024-25 के लिए कृषि विभाग का बजट आवंटन 1,32,470 करोड़ रुपये है जो वर्ष 2013-14 में महज 27,663 करोड़ रुपये था। चौहान ने कहा कि अगर संबद्ध मंत्रालयों और उर्वरक सब्सिडी को मिलाकर देखा जाए तो ये आंकड़े और भी ज्यादा होंगे।

उन्होंने इन आरोपों को भी सिरे से खारिज कर दिया कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर किसानों से पर्याप्त अनाज नहीं खरीद रही थी। उन्होंने कांग्रेस और इसके नेता राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वे महाभारत में केवल 'शकुनि, चौसर और चक्रव्यूह' को याद करते हैं जो अधर्म को दर्शाता है लेकिन 'हम केवल भगवान कृष्ण को याद करते हैं।'

कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र को नजरअंदाज किया गया और कांग्रेस के शासन काल में प्राथमिकताएं कुछ और थीं।

वैश्विक कृषि अर्थशास्त्रियों का सम्मेलन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 32वें इंटरनैशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकॉनमिस्ट का उद्घाटन करेंगे, जिसका आयोजन भारत में 65 वर्षों के बाद हो रहा है। इसमें करीब 75 देशों से 1,000 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसका लक्ष्य जलवायु परिवर्तन, बढ़ती उत्पादन लागत जैसी वैश्विक चुनौतियों के बीच टिकाऊ खेती की जरूरत पर जोर देना है।